[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

पिछले दिनों राजस्थान के गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में कई पाकिस्तानी नागरिकों तथा तस्करों को पकड़ा गया।

अतः मान्यवर, रक्षा मंत्रलय का ध्यान में इन गतिविधियों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान इसी हिस्से से आगे बढ़ता है। अतः इन गतिविधियों की ओर ध्यान दिया जाए।

(ii) REPORTED STATEMENT OF DELHI POLICE COMMISSIONER AGAINST THE FINDINGS OF A COMMISSION RE. BAGHPAT INCIDENT.

श्री मनोराम बागड़ी : (हिसार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी डैमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी है।

MR. DEPUTY SPEAKER: You are very embodiment of democracy itself!

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बागपत कांड के जांच आयोग की रपट को सार्वजनिक रूप से भर्त्सना और नारी जगत का अपमान किया है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि तीन व्यक्तियों को, जो पूर्णतया निर्दोष थे, पुलिस ने अकारण मारा। वे डकैत नहीं थे। माया त्यागी एक सुशील महिला थी। उस के गुप्त अंग में 6—7 टांके लगे हैं। उस से डकैतों का कोई रिश्ता नहीं था। श्री विनोद मुजफ्फर नगर में पुलिस कांस्टेबिल थे, इनके बड़े भाई की हत्या बागपत थाने की पुलिस ने की और इन की भाभी को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया। यदि विनोद त्यागी के मस्तिष्क पर अपने भाई की हत्या और भाभी की सार्वजनिक बेइज्जती की कोई प्रतिक्रिया हुई हो और उस ने बदले की भावना से कोई काम किया हो, तो सम्पूर्ण त्यागी समाज को कहना कि त्यागी गैंग है" पूर्णतया असंवैधानिक है और एक जाति विशेष को कलंकित करना है। गृह मंत्री को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुला कर उनकी भर्त्सना करनी चाहिए और उन को बर्खास्त कर देना चाहिए।

(iii) NEED TO ACCORD PRIORITY IN ALLOTMENT OF RAILWAY WAGONS FOR TRANSPORTATION OF FOODGRAINS BY KERALA STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION.

SHRI A. K. BALAN (Ottapalam): Even though the public distribution system in Kerala is well organised, there is shortage of supply of ration articles due to non-availability of stock. For the distribution of foodgrains at the present rate, the requirement of rice and wheat is 1.94 lakh tonnes and 10,000 M.T. respectively. Against this, the allotment sanctioned is only 1.35 lakh tonnes of rice and 4,000 M.T. of wheat and only 80,000 tonnes were actually being received.

In order to ensure regular availability of foodgrains during the lean months of the monsoon season it is necessary that sufficient buffer stock is built up. But the efforts made by the State Government and FCI in this regard are yet to give results. The FCI is finding it difficult to move the 1.35 lakh tonnes of rice allotted to the State in a month and the stock position in most FCI godown is very meagre. Delayed arrival and release of stock lead to public complaints and also give private dealers opportunity to exploit the situation to their advantage.

Kerala State Civil Supplies Corporation has a major role in maintaining the supply of foodgrains and other articles, but due to non-availability of sufficient wagons the Corporation is facing the problem of transporting the foodgrains procured from the neighbouring States. At present the priority in allotment of wagons is given only for lifting foodgrains for FCI. It is necessary that this priority is extended to the K.S.C.S.C. also so that the activities of the Cor-

poration do not suffer for want of wagons facilities. We request the Hon. Minister to issue orders for ensuring the allotment of sufficient quantity of foodgrains to the State and priority for transporting the same by rail.

(iv) REPORTED DISCONTENTMENT AMONG THE CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES OF RANIKHET IN UTTAR PRADESH DUE TO NON-SANCTION OF HOUSE RENT ALLOWANCE TO THEM.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : रानीखेत, उत्तर प्रदेश जो कि एक पर्वतीय स्टेशन है, यहां कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में हाउस रेंट एलाउंस न दिये जाने के कारण बहुत असंतोष और निराशा व्याप्त है। रानीखेत जैसी भोगोलिक परिस्थितियों वाले अन्य पर्वतीय स्टेशंस में कार्यरत कर्मचारियों को केन्द्र सरकार यह सुविधा दे रही है जब कि यहां नहीं दे रही है। तीसरे वेतन आयोग द्वारा इस स्टेशन को एच आर ए के लिए शामिल न किए जाने के कारण इस स्टेशन में कार्यरत कर्मचारी इस सुविधा से वंचित रह गए हैं। यह उचित नहीं है। अतः यह सरकार का कर्तव्य है कि वेतन आयोग की इस भूल को सुधारे तथा रानीखेत के केन्द्रीय कर्मचारियों को भी हाउसरेंट एलाउंस प्रदान करे।

मैं समझता हूं कि एच आर ए का वर्तमान रेट कम है, इसे बढ़ा कर 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

उ० प्र० सरकार अपने कर्मचारियों को जो कि 8 पर्वतीय जिलों में कार्यरत हैं वेतन प्रलोभन के पर्वतीय विकास भत्ता देती है जब कि उन की स्थिति में ही कार्यरत केन्द्रीय कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं दिया जाता। अतः उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों में कार्यरत केन्द्रीय कर्मचारियों को भी दस प्रतिशत पर्वतीय विकास भत्ता दिया जाय।

मैं उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही हेतु माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं।

(v) NEED TO OPEN KENDRIYA VIDALAYA IN GHAZIPUR, UTTAR PRADESH.

श्री जैनूल बशर (गाजीपुर) : सरकार की यह नीति है कि जहां भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं वहां केन्द्रीय विद्यालय खोला जाय जिस से कि कर्मचारियों के लड़के लड़कियां की शिक्षा सुचारु रूप से हो सके। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में केन्द्रीय सरकार का अफीम का एक बड़ा कारखाना है जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। वहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की बहुत दिनों से मांग होती रही है परन्तु अभी तक सरकार ने इस मांग को नहीं माना है। इस से उन के लड़के लड़कियों की शिक्षा सुचारु रूप से नहीं हो पाती और स्थानान्तरण के समय शिक्षा में बाधा पड़ती है।

मेरा शिक्षा मंत्री से आग्रह हैं कि शीघ्रातिशीघ्र गाजीपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था करें।

(vi) ACUTE SHORTAGE OF WATER AND FAMINE CONDITIONS EXISTING IN DISTRICTS OF PALAMAU, HAZARIBAGH AND GAYA IN BIHAR.

SHRI RANJIT SINGH (Chatra): There is acute hortage of water and famin conditions exist in the districts of Palamau and Hazaribagh and a portion of Gaya in Bihar.

The people in the districts of Palamau and Hazaribagh and a portion of Gaya in Bihar are facing acute shortage of water.

Earlier their 'Bhadai' crops were damaged due to heavy rain and now paddy plantation has suffered due to lack of rain and water. The area is now famine-stricken and a large-number of people in the villages face starvation. The plight of the cattle too is miserable.